

एमबीबीएस में एडमिशन होगा कॉमन एंट्रेस से

सीईटी पर राजी हुए कॉलेज, 2012-13 से लागू



► स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में किया गया फैसला

► एम्स को भी सीईटी के दायरे में लाने पर किया जा रहा है विचार

► देशभर में एमबीबीएस के लिए एक टेस्ट लागू करना है मकसद

► मेडिकल एजुकेशन का नया पाठ्यक्रम भी जल्द अंतिम रूप ले लेगा

कौन्तेय सिन्हा || टीएनएन

मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले लोगों को अगले साल से एक कॉमन एंट्रेस टेस्ट (सीएटी) देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) वर्ष 2012-13 के अकेडमिक सेशन के दौरान सभी सरकारी

और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के लिए सीईटी अनिवार्य करने पर सहमत हो गए हैं।

एमसीआई अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि सोमवार को स्वास्थ्य सचिव के चंद्रमोली की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इस मीटिंग में सीबीएसई और एमसीआई के कई अन्य अधिकारी

भी मौजूद थे। इसमें करीब 8-10 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। चंद्रमोली ने बताया कि वे इस टेस्ट के प्रारूप पर विचार कर रहे हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि मीटिंग में एम्स जैसे संस्थानों में भी सीईटी लागू करने पर चर्चा की गई। सीईटी के लागू होने से एम्स को अपने अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अलग से एंट्रेस एग्जाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीईटी में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स एम्स में पढ़ सकेंगे। हालांकि अभी इस मसले पर अभी और चर्चा होगी।

इस सारी कवायद का मकसद देशभर में एक मेडिकल एंट्रेस एग्जाम लागू करना है। एमसीआई का नया बोर्ड मेडिकल एजुकेशन के उस नए पाठ्यक्रम पर भी विचार कर रहा है, जो पुराने बोर्ड ने तैयार किया था। एमसीआई की गवर्निंग बोर्डी के एक मेंबर ने बताया कि हम इस रिवाइज्ड पाठ्यक्रम को जल्द ही अंतिम रूप देंगे। हम इसे अपनी वेबसाइट पर जारी करेंगे, ताकि लोग इस पर अपने सुझाव और आपत्ति जाहिर कर सकें।

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह एंट्रेस एग्जाम देश के सभी 271 मेडिकल कॉलेजों में चल रहे एमबीबीएस कोर्सों के लिए लागू होगा। इनमें से 138 सरकारी और 133 प्राइवेट कॉलेज हैं। इन सभी कॉलेजों में 31,000 सीटें हैं।